of the Government as well as the process of planning so as to make planning largely indicative. Liberalisation of the economy is consistent with indicative planning. The Planning Commission will have to concentrate on anticipating future trends and evolving integrated strategies for achieving the highest possible level of development of the country in keeping with the internationally competitive standards. This will call for the creation of a culture of high productivity and cost efficiency in the Government both at the Centre and in the States, and the Planning Commission will have to play the role of a catalyst.

Analysis made by Planning Commission Regarding Macro-Economic Imbalances

378. SHRI MENTAY PADMANA-BHAM: Will the MINISTER OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has initiated any indepth analysis of the causes of the recent macro-economic imbalances ; and

(b) whether the Planning Commission has been asked by the Finance Ministry for its reaction for smooth integration of the economy with the global system ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) and (b) The cause of macro-economic imbalances have been studied in preparing the Eighth Five Year Plan and the annual Plans. The growing fiscal gap and depletion of foreign exchange resources created a situation which put severe strain on the economic system leading to import curbs, high rate of inflation and recession in industry. Corrective measures have been initiated under the Eighth Five Year Plan, which also stipulated a reformed policy regime on trade, technology, transborder capital flows and financial sector. These will smoothen the integration of the Indian economy with the global system.

संसद-सदस्यों का मंत्रालयों से पत्राचार

379. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सासदों द्वारा मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गये और उनका वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों को पावती भेजी गई;

(ग) कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर भेजे गये; और

(घ) मंत्रालय द्वारा क्रमश: सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर वाले भेजे गये अन्तिम पत्रों के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

देश में गरीबी के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिया गया सर्वेक्षण

380. **श्री जीवन राय** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिये गये संकलन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने स्वर्गीय प्रो० डी० के० लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के अनुसार कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं; और